उद्योग व बुनियादी सुविधाओं पर जोर के साथ सक्रिय हुई सरकार

अमर उजाला ब्यूरो

चुनाव खत्म होते ही रोजगार के लिए उद्योगों पर प्रदेश सरकार का फोकस

लखनऊ। करीब ढाई महीने लंबे चुनावी सीजन के बाद प्रदेश सरकार पुनः मुस्तैद हो गई है। चुनाव में बेरोजगारी के बड़े मुद्दे को देखते हुए सरकार का सारा फोकस ज्यादा से ज्यादा औद्योगीकरण और बुनियादी ढांचे के विकास पर है। निवेशक सम्मेलन में आए प्रस्तावों को लक्ष्य देकर धरातल पर उतारने का काम शुरु कर दिया गया है। इसी तरह नए औद्योगिक कॉरिडोर के जरिये युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोलने की रणनीति पर काम हो रहा है।

चुनाव परिणाम घोषित होने के तत्काल बाद प्रदेश में रुके कामों को रफ्तार देने का सिलसिला शुरू हो गया है। बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सिलसिले में बैठक भी बुलाई थी। प्रदेश में कामकाज का पहला फोकस बुनियादी सुविधाओं के विकास, युवाओं को रोजगार और निवेश प्रस्तावों को जल्द से जल्द धरातल पर उतारना है।

गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को समय सीमा के अंदर तैयार करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यूपी से गुजरने वाले अमृतसर-कोलकाता कॉरिडोर के लिए जमीन के अधिग्रहण में कोताही न बरतने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस कॉरिडोर के दो नोड आगरा और प्रयागराज में विकसित होने हैं। इससे इन दोनों जिलों के साथ ही आसपास के दस जिलों को भी जबरदस्त फायदा होगा।

भूमि पूजन समारोह के बाद उन प्रस्तावों को जल्द से जल्द जमीन पर उतारा जाएगा, जो लगभग तैयार हैं और चुनाव की वजह से विलंब हो गया था। खास तौर पर पूर्वांचल और बुंदेलखंड में निवेश के लिए जिन कंपनियों से करार किया गया है, उन्हें शीघ्र इकाई लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा।